

जय किसान : नीति आयोग ने तैयार किया रोडमैप, किसान की आय बढ़ेगी नई कृषि क्रांति की तैयारी... अब ड्रोन, एआइ और रोबोट से होगी खेती

कृषि लागत को 40 फीसदी घटाने और उत्पादन में 60% वृद्धि का अनुमान

कानाराम मुण्डियार
patrika.com

नई दिल्ली. यदि केंद्र सरकार की योजना परवान चढ़ी तो देश में कृषि अब हल-बैल से नहीं, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), रोबोट और बीजों की जीन एडिटिंग से होगी। पानी की बर्बादी शून्य होगी और भरपूर पैदावार से किसान की आय मौजूदा स्तर से दोगुनी हो सकती है। नीति आयोग ने देश में खेती की दिशा और दशा बदलने के लिए अगले पांच साल के लिए नया रोडमैप जारी किया है।

नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट 'रीडिफाइनिंग एग्रीकल्चर : रोडमैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लीड ट्रांसफॉर्मेशन' के रूप में अगले पांच साल का रोडमैप तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट में कृषि में 100 फीसदी आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऐसी तकनीकों को चुना है, जिसके जरिए देश की कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। ये तकनीकें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, मिट्टी की थकान और बाजार की अनिश्चितता को खत्म करने में मददगार बनेंगी। रोडमैप पर प्रभावी अमल से अगले 5 साल (2026-30) में देश में कृषि लागत 40 प्रतिशत घटने का अनुमान जताया गया है। कृषि लागत को ही किसानों की खुशहाली और खेती को लाभकारी बनाने में सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। रोडमैप से कृषि उत्पादन में 60% बढ़ोतरी होगी।

फ्रंटियर टेक्नोलॉजी : खेत से लैब तक

ड्रोन फार्मिंग

1 घंटे में 50 एकड़ पर कीटनाशक छिड़काव, 80% दवा बचत।

रोबोटिक्स

बुवाई, निराई, कटाई सब ऑटोमैटिक, मजदूरों की कमी दूर।



एआइ/एमएल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग: मौसम, कीट, बीमारी का 100% सटीक पूर्वानुमान।

■ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी) : मिट्टी की नमी, पीएच, पोषक तत्व 24 घंटे सातों दिवस मोबाइल पर।

■ सैटेलाइट इमेजरी : बादल पार कर फसल की लाइव तस्वीर, सूखा-बाढ़ अलर्ट।

■ जीन एडिटिंग (सीआरआइएसपी आर) : 2 साल में सूखा, कीट, नमक रोधी नई किस्में।

■ बिग डेटा एनालिटिक्स : हर गांव, हर फसल का अलग 'डिजिटल फॉर्मूला'।

■ ब्लॉकचेन : बीज से बाजार तक पारदर्शी चेन, नकली खाद व बीज खत्म।

■ प्रिसिजन फार्मिंग : हर पौधे को अलग खाद-पानी, 30% लागत में होगी बचत।

■ वर्टिकल फार्मिंग : शहरों में की छतों पर 10 मंजिला खेत, 1 एकड़ यानी 10 एकड़ यील्ड पर फॉर्मिंग।

■ हाइड्रोपोनिक्स : बिना मिट्टी, 90 प्रतिशत कम पानी, साल भर फसल।

■ एरोपोनिक्स : पानी की बूंद भी बर्बाद नहीं।

साल दर साल ऐसे हासिल करेंगे लक्ष्य

2026 : पायलट प्रोजेक्ट

■ 10 राज्यों में ड्रोन एआइ हब, एक लाख एकड़ कवर

2027 : डिजिटल पहुंच

■ 50% किसानों को मुफ्त ऐप, सैटेलाइट डेटा, आइओटी किट मिलेंगे

2028 : ग्लोबल मार्केट

■ ब्लॉक चेन से सीधे निर्यात, 10 लाख टन ऑर्गेनिक

2029 : रोबोट क्रांति

■ 500 रुपए/दिन रोबोट किराया, 50,000 यूनिट डिप्लॉय

2030 : स्मार्ट विलेज

■ हर गांव में 'डिजिटल खेत', आय दोगुनी की गारंटी

फंडिंग-इंफ्रास्ट्रक्चर का यह रहेगा मॉडल

■ कृषि-टेक फंड : ₹50,000 करोड़

■ ड्रोन दीदी : एक लाख महिलाओं को ट्रेनिंग।

■ एआइ लैब : हर जिले में एक एआइ लैब बनेगी।

■ फ्री स्मार्टफोन : 10 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे

■ रोबोट बैंक : 1 लाख यूनिट रेंट पर खुलेगा।

सब साथ आएंगे तभी होंगे सफल



यह तभी सफल होगी जब किसान, वैज्ञानिक, उद्यमी, निवेशक और नीति-निर्माता एक साथ आएंगे। तकनीक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, खेतों तक पहुंचे। यह रोडमैप ऐसे भविष्य का एक आह्वान है, जहां भारत विश्व का अन्न भंडार बने। -बी.वी.आर.सुब्रह्मण्यम, सीईओ, नीति आयोग

किसानों को ऐसे होगा लाभ

■ आय: 1 एकड़ में गेहूं से मौजूदा 25,000 रुपए से बढ़कर 2030 में 70,000 रुपए
■ लागत कम: 40% कम होगी (खाद-पानी-दवा)

■ उत्पादन बढ़ेगा: 60% बढ़ेगा
■ पानी बचत : 90% (हाइड्रो/एरोपोनिक्स)
■ बाजार उपलब्धता: 100% (ब्लॉकचेन)